फरवरी 2025
वर्ष 39 संख्या 2
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

मोगा रैली द्वारा संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित एमएसपी गारंटी कानून खारिज, एनपीएफएएम के खिलाफ आंदोलन का ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब के आवाह्न पर 9 जनवरी को मोगा में एक विशाल महापंचायत की गई। इसमें लगभग 50 हजार किसानों ने भाग लिया। ये किसान पंजाब के कोने–कोने से आये थे। मोगा महापंचायत ने संसदीय स्थाई समिति द्वारा प्रस्तावित एमएसपी गारंटी कानून को खारिज किया।

मोगा महापंचायत ने कृषि उत्पाद की बिक्री पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 13 जनवरी को तहसील मुख्यालयों पर इस दस्तावेज की प्रतियां जलाने तथा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान किया गया। महापंचायत ने मांग की कि पंजाब सरकार विधानसभा की बैठक बुलाकर नई कृषि विपणन नीति को खारिज करे।

महापंचायत ने नई कृषि विपणन नीति के मसौदे को खारिज करने तथा किसानों की मांगों के समाधान के लिए किसान आंदोलन की व्यापक एकता का आह्वान करने का संकल्प लिया। महापंचायत में घोषणा की गई कि एसकेएम की 6 सदस्य एकता समिति 10 जनवरी को मोगा महापंचायत का एकता प्रस्ताव लेकर खनोरी तथा शंभू सीमा पर जाएगी तथा संयुक्त बैठक का आमंत्रण देगी।

महापंचायत ने मांग की कि आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार संघर्षरत किसान संगठनों से बातचीत करे। एसकेएम ने जोर देकर कहा है कि केंद्र सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्री जगजीत सिंह दल्लेवाल की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।

मोगा महापंचायत में कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा को खारिज करने के साथ स्वामीनाथन फार्मूले पर एमएसपी और खरीद के लिए कानूनी गारंटी देने और केंद्र सरकार के साथ दिल्ली समझौते के सभी सहमत बिंदुओं को लागू करने व सभी किसानों और श्रमिकों के लिए कर्ज माफी की मांग की।

महापंचायत ने घोषणा की कि कृषि विपणन पर नई राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा पूर्व में निरस्त किए गए तीन काले कृषि कानूनों का ही एक संस्करण है। मोर्चा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर साम्राज्यवादियों के लिए और संघीय कामकाज के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन और सरकार के कॉरपोरेट मित्रों की नीतियों ने भारत के किसानों पर नए सिरे से हमला किया है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से संघीय सिद्धांतों की रक्षा करने और विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके इस मसौदे को खारिज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों को इसमें पहला लेते हुए आगे आना चाहिए।

महापंचायत में किसान नेताओं ने इन सवालों के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूत और एकजुट आंदोलन चलाने के लिए संगठनों को तैयार रहने की अपील की। महापंचायत के नेताओं ने कहा कि संसद की स्थाई समिति ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को भूलकर एमएसपी और खरीद गारंटी पर अधूरी सिफारिश की है। इसे खारिज करते हुए एस.के. एम. ने कहा कि वह एमएसपी की मांग के लिए लंबे समय तक आंदोलन के लिए तैयार है। महापंचायत को बलबीर सिंह राजेवाल, जोगेंद्र सिंह उग्राहां, राकेश टिकैत, हरमीत सिंह कादियान, डा. दर्शन पाल, रमिंदर सिंह पटियाला, कृष्ण प्रसाद, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लाखोवाल, मनजीत सिंह धनेर, डा. सतनाम सिंह अजनाला, पुरुषोत्तम शर्मा, बलदेव सिंह निहालगढ़, रूलदू सिंह मानसा, राजन श्री सागर और श्री जोगिंदर नैन सहित कई अन्य किसान नेताओं ने संबोधित किया।

ट्रम्प सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार

भारत सरकार की खामोशी की कड़ी निंदा

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी अमेरिकी सरकार द्वारा निर्वासित भारतीय युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने और इसमें भारत सरकार की मिली भगत की कड़ी निंदा करती है। अवैध अप्रवासी होने के कारण अमेरिका सरकार द्वारा निर्वासित 104 भारतीयों जिसमें युवा महिला और बच्चे भी शामिल हैं, 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे। अब यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि 24 घंटे से अधिक की पूरी यात्रा के दौरान उन्हें खतरनाक अपराधियों की तरह हसथाके में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगाई गई थीं। ऐसी ही स्थिति में कोलंबिया जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति ने निर्वासित लोगों के साथ ऐसे व्यवहार में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस असम्मानजनक व्यवहार का विरोध करने के बजाय विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया के रूप में उचित ठहरने की कोशिश की है। भारत के पीएम मोदी की किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का प्रबंध करवाना देश के स्वाभिमान और भारतीयों की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

यह अवैध अप्रवासी युवा इतनी तकलीफें और खर्च उठाकर अमेरिका अपनी मर्जी से नहीं जाते बल्कि इसलिए जाते हैं, क्योंकि भारत में उन्हें रोजगार के उचित अवसर नहीं मिलते। विभिन्न नारों और जुमलों के अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और बेरोजगारी दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार अब एजेंटों और दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने का शोर मचा रही है, जबकि वह कई सालों से इस अवैध अप्रवासी रैकेट को अनुमति देती रही है। यह भी आश्चर्य की बात है कि विमान अमृतसर में ही क्यों उतरा, जबकि सबसे ज्यादा निर्वासित लोग गुजरात से थे। क्या यह पंजाबियों की एकतरफा छवि बनाने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास नहीं है ?

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी सरकार से मांग करती है कि–

–भारत सरकार निर्वासितों के साथ किए गए अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ खुलकर अपना कड़ा विरोध दर्ज करे और निर्वासितों को लेकर आने वाले किसी भी अमेरिकी विमान को उतारने की अनुमति देने से इंकार करे, जब तक की यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उन्हें मानवीय और सम्मानजनक तरीके से लाया जा रहा है।

–अमेरिका से लौटे युवाओं के परिवारों को हुए वित्तीय नुकसान की पूरी भरपाई के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे, क्योंकि इस प्रकार का पलायन सरकार की विफलता के कारण होता है।

–सरकार जिम्मेदार एजेंटों और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी शक्तियों के अधीन होने और विदेशी पूंजी पर निर्भर होने के बजाय सरकार को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने और हमारे देश के युवाओं को सार्थक रोजगार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

(सीपीआई (एमएल) - न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 6 फरवरी 2025 को जारी)

आदिवासियों की हत्या, खनिज जमीन को कारपोरेट को सौंपने की साजिश 'आपरेशन कगार' का विरोध

आंध्र प्रदेश में 'ऑपरेशन कगार' के खिलाफ आयोजित गोलमेज बैठक में 13 फरवरी को राज्य स्तरीय संयुक्त विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया है। 3 फरवरी 2025 को विजयवाड़ा के प्रेस क्लब में सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की पहल पर आयोजित गोलमेज बैठक में वामपंथी राजनीतिक दलों, जन संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों व मंचों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों से निम्नलिखित मांगों के साथ संयुक्त रूप से एकदिवसीय विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि ऑपरेशन कगार को बिना शर्त वापस लिया जाना चाहिए इसके लिए 13 फरवरी को राज्यव्यापी धरना और विरोध कार्यक्रमों का आह्वान किया गया है।

गोलमेज बैठक की आयोजक सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार की मंशा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक नोट भी प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि जंगलों में नरसंहार कोई माओवादी समस्या अथवा आदिवासी समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के सभी लोगों की समस्या है।

दस्तावेज में कहा गया है कि –

1– हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि केंद्र सरकार ने भारत के विशाल वन क्षेत्र को बड़े कॉरपोरेट के लिए हड़पने के

(शेष पृष्ठ 8 पर)

रोजगार की तलाश में गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि के गांव के गांव हो रहे हैं वीरान

गहन है अंधकारा... सब दांव पर लगा विदेश भाग रहे युवा

अनिल दुबे

'गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से, हुआ है लुंठन हमारा।' सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता आज देश के मौजूदा हालात में बहुत मौजू है।

देश निराशा के समंदर में गोते लगा रहा है ! क्या गरीब, क्या निचला मध्यम और मध्यम वर्ग या फिर छात्र, मजदूर, किसान, युवा और मझोले व्यापारी सभी के लिए रोजी–रोटी और अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट हाल के वर्षों में निरंतर गहराता जा रहा है। आरएसएस–भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में नौकरी, स्वरोजगार और व्यापार के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का निम्न और मध्यम वर्ग का सपना चकनाचूर हो चुका है। यही कारण है कि बीते 10 वर्षों में देश से वैध और अवैध ढंग से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में जाकर काम–धंधा और रोजगार करने वालों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। युवाओं का सपना अब देश में पूरा होना नामुमकिन सा हो चुका है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में शिक्षित, कम पढ़े लिखे युवा और श्रमिक भी अवैध ढंग से जिसे इस कारोबार में लगे लोग 'डंकी रूट' कहते हैं रोजगार के लिए विदेश भाग रहे हैं। इसके लिए वह घर, जमीन और परिवार की समस्त जमा पूंजी बेच कर अथवा कर्ज लेकर 40–50 से लेकर 80 लाख और करोड़ रुपए तक खर्च कर, अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा कर विदेश भाग रहे हैं। वहीं आरएसएस–भाजपा सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाली दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का सब्जबाग जनता को दिखा रही है, लेकिन मिडिल क्लास को उसके इस वायदे पर यकीन नहीं है।

2015–16 तक जहां कुछ हजार लोग ही अमेरिका, कनाडा और यूरोप का रुख करते थे। वहीं 2023 आते आते यह संख्या प्रतिवर्ष लाखों से अधिक हो गई है। अमेरिकी संस्था (आईसीई) के मुताबिक वर्ष 2023 में 3 लाख 86 हजार लोगों को एच–1 वीजा दिया गया, जिसमें तीन चौथाई भारतीय हैं। उसने 15 लाख अवैध प्रवासियों की सूची बनाई जिसमें 18000 भारतीय हैं। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक उसके यहां रह रहे 10 करोड़ अवैध प्रवासियों में से लगभग 7 लाख 25 हजार अवैध प्रवासी भारतीय हैं। यह अवैध प्रवासी बीते वर्षों में ज्यादातर डंकी रूट से गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया कनाडा और दूसरे यूरोपीय देशों में भी लाखों लोग अवैध तरीकों से ही बीते 10 वर्षों में वहां का रुख कर चुके हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि देश भर से मध्यम वर्ग के लोग विदेशों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की है। दक्षिण भारत व अन्य राज्यों के लोग हायर एजुकेशन अथवा हायर प्रोफेशनल डिग्री के बाद एक खास पोजीशन की नौकरी के लिए विदेश गए हैं या जा रहे हैं, लेकिन पंजाब, गुजरात और अब हरियाणा व राजस्थान ऐसे राज्य हैं, जहां निम्न और मध्यम वर्गीय तबका अपनी जिंदगी के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगाकर विदेश जा रहा है।

खास बात यह है कि पंजाब जो कभी देश के एक बड़े हिस्से को रोटी खिलाता था, हरियाली तो आज भी वहां है, लेकिन उदासी भी है, क्योंकि वहां हीर–रांझा के गीत और टप्पे गाने वाले मतवालों की टोली नहीं है। अमृतसर, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, फिरोजपुर, नवांशहर जैसे कई जिलों के गांव में युवा लड़के लड़कियां दिखाई नहीं देते। गांव के गांव नौजवानों से सूने पड़े हैं। एनआरआई बन चुके युवाओं के डॉलर्स और पाउंड्स से बड़े–बड़े हवेली नुमा घर बन चुके हैं, लेकिन उन घरों में उदास बूढ़ी आंखें विदेशों में सेट हो चुके बच्चों का इंतजार करती हैं या बदहाल घरों के आंगन में हाल फिलहाल में कर्ज का बोझ छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने गए बेटे–बेटियों की भली चंगी खबर सुन लेने के लिए तरसते नजर आते हैं।

इसी तरह गुजरात जिसको आरएसएस–भाजपा सरकार के विकास के मॉडल के रूप में दो दशकों से दिखाया जाता रहा है, वहां के भी कई जिलों की स्थिति भयावह है। गांधीनगर का डींगुचा गांव की 7000 की आबादी में से आधे लोग विदेश में बसे हैं। इसी गांव के डंकी रूट से कनाडा जाते हुए पिछले वर्ष एक परिवार के चार लोग, जिनमें दो छोटे बच्चे थे,– 35 डिग्री की ठंड में मृत पाए गये। आणद, मेहसाणा आदि जिलों के गांव के गांव खाली पड़े हैं। यहां भी मिडिल क्लास खासतौर पर पटेल जाति जिसका बड़ा हिस्सा संपन्न तबका है, विदेशों का रुख दशकों से करता रहा है। वैसे भी पंजाब और गुजरात से काम–धंधे और नौकरी के लिए प्रवासन कई दशकों से चल रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में वह तेजी से बढ़ा है।

पंजाब से हो रहे प्रवासन पर एक अध्ययन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्मेंट आफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी ने किया, जिसके मुताबिक पंजाब में 30 सालों में बड़ी संख्या में युवा विदेश में जाकर बस गए। 2016 के बाद हर परिवार ने 3.13 लाख रुपए का कर्ज लिया और इस दौरान सबसे ज्यादा 74 प्रतिशत लोग 2016 के बाद गए हैं। अध्ययन के अनुसार विदेश की शरण लेने वालों में ज्यादातर निचली जातियों या कम आय वर्ग के लोग थे, जिन्होंने अपनी छोटी सी जमीन, घर, सोना, ट्रैक्टर और अन्य संपत्तियां बेचकर विदेश का रुख किया। पंजाब के 13.34 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में कम से कम एक सदस्य विदेश में बस गया है। इसमें से 42 प्रतिशत लोग कनाडा, 16 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया, 10 प्रतिशत इटली, 6 प्रतिशत यूरोप के अन्य देशों में और 3 प्रतिशत इंग्लैंड गए हैं। यह अध्ययन 22 जिलों के 44 गांव 9492 हजार घरों में से 640 प्रवासियों और 660 गैर प्रवासी परिवारों का साक्षात्कार करके किया था। प्रवासन के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 1990 से सितंबर 2022 का समय चुना गया था। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर और फिरोजपुर जिलों में विदेश जाने वालों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है। तीन चौथाई परिवारों ने विदेश जाने का मुख्य कारण रोजगार के अवसर की कमी, कम वेतन का रोजगार, भ्रष्ट व्यवस्था और कम आय जैसे मुद्दे बताए। दोआबा क्षेत्र के ये पुरुष भूमिहीन, कम शिक्षित और अनुसूचित जाति के थे, जो वर्क परमिट लेकर संयुक्त अरब अमीरात गए, जबकि माझा और मालवा के सभी तरह की कृषि जोत वाली श्रेणियां के परिवारों के युवाओं ने अध्ययन के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चुना। खासतौर से जाट सिख युवाओं के लिए वहां पढ़ना और फिर विदेश में सेट हो जाना एक बड़ा सपना है। अध्ययन वीजा पर जाने वालों में 65 प्रतिशत महिलाएं और 35 प्रतिशत पुरुष थे। 19.38 प्रतिशत प्रवासी ऐसे थे, जिन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी। यही नहीं 56 प्रतिशत परिवारों ने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए बड़ी रकम उधार ली।

एक दशक में देश के अधिकांश व्यवसायिक कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां के लिए लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार में धांधली व पेपर लीक जैसे बढ़ते मामलों से युवाओं के बीच संकट और गहरा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की लगभग डेढ़ करोड़ नौकरियां के पद रिक्त हैं, लेकिन कई–कई वर्षों में कुछ हजार वैकेंसी ही निकाली जाती है। फिर भी उनके पर्चे आउट हो जाते हैं। जेई का नेशनल एग्जाम नेट, रेलवे भर्ती और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्र और युवा आंदोलन के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करते रहते हैं। ऐसे में करोड़ों शिक्षित–अशिक्षित युवाओं और छात्रों को महसूस होने लगा है कि अब देश में उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। यही कारण है कि वह किसी भी तरह से दूसरे देशों में जाकर नौकरी करने का रास्ता अपना रहे हैं। अग्नि वीर योजना के चलते सेना में भर्ती का भी सपना ग्रामीण युवाओं का टूट चुका है। यही कारण है कि हरियाणा और राजस्थान के युवा भी बीते वर्षों से विदेश प्रवास की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ताजा उदाहरण हरियाणा के करनाल का है, जब वहां से गए युवाओं में से एक अमित कुमार ने डंकी रूट अपनाया और 42 लाख रुपए खर्च किए घने जंगलों, बर्फीले रास्तों और अपराधी गिरोहों के बीच वह पनामा के जंगलों से पैदल गये और एक दुर्घटना में विकलांग हो गए। हरियाणा व राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं।

यह गौरतलब है कि 40–50 लाख से लेकर 80–90 लाख रुपए तक खर्च करने और खतरनाक रास्तों से जान हथेली पर लेकर अवैध और डंकी रूट से विदेशों में बसने की चाह रखने वाले भारतीय युवा आखिर भारत में ही अपना भविष्य क्यों नहीं देख पा रहे हैं ? इसकी बड़ी वजह है कि यह छोटी जोत वाले किसानों के बच्चे हैं। सरकारों द्वारा खेती को अलाभकारी बना देने के कारण कृषि में उसे अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लाखों की इस पूंजी से वह स्वरोजगार भी कर सकता है, लेकिन उसकी भी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि लघु स्तर के उद्योग या अन्य छोटे कारोबार चलने की संभावना समाप्त हो गई है। लाखों–लाख की आबादी द्वारा यदि छोटा उद्योग या बिजनेस शुरू भी किया जाय, तो उसके लिए मार्केट में खरीदार नहीं है। एक बड़ी आबादी की खरीद क्षमता नहीं रह गई है। काम–धंधे और रोजगार को लेकर घोर निराशा का वातावरण है। एमएसएमई सेक्टर नोट बंदी, जीएसटी और कोरोना लॉक डाउन की मार से ध्वस्त हो चुका है। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया व स्टार्टअप योजनाएं जमीनी हकीकत नहीं बन सकीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अवैध ढंग से विदेश पहुंचे लोगों को काम–धंधा बीते दशकों में वहां पहले से बस चुके भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित कारोबार में ही मिलता है। विदेशों में सरकारी वेज अधिक है, लेकिन भारतीय बिजनेसमैन कम वेतन में अवैध रूप से गए युवाओं से काम लेते हैं। यह अलग बात है कि वह फिर भी भारत की मजदूरी दर या वेतन से बहुत अधिक होता है। कम शिक्षित लोगों को ज्यादातर होटल में बैरा, दुकानों में सेल्समैन, ट्रक ड्राइवर, साफ–सफाई कर्मी या घरेलू काम के लिए रखा जाता है और वहां उनके शोषण की एक अलग ही दास्तान है।

धन और जान को खतरे में डालकर किसी तरह अमेरिका पहुंच गए लोगों के लिए बड़ा संकट नरेंद्र मोदी के कथित दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के जरिए पैदा हो गया है। हालांकि दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने ट्रंप ने 'मित्र मोदी' को ताजपोशी में नहीं बुलाया, लेकिन अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को निकालने की उनकी अनाप–शनाप और संविधानेत्तर घोषणाएं अवैध भारतीय प्रवासियों के हितों पर चोट है। 18000 भारतीय जो गिरफ्तार हैं या पुलिस की निगरानी में आ चुके हैं, उनकी वापसी की बात है। इसके अलावा अन्य लाखों लोगों को भी हटाने की चर्चा है। इसके कारण गुजरात, पंजाब व अन्य राज्यों के उन गांवों में भय का वातावरण बन गया है, जहां के लोग अवैध ढंग से अमेरिका में रह रहे हैं। एच–1 वीजा और वर्क परमिट पर गए लोगों में भी दहशत का माहौल है। यही नहीं बहुत सारे लोग जो अभी जाने की तैयारी में हैं, उनके सपनों पर भी गाज गिरी है।

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए। इनमें से काफी लोग वापस भेज दिए गए और बाकी हिरासत में लिए गए हैं। अमेरिका द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के 1 वर्ष के दौरान 96917 भारतीयों को बगैर दस्तावेज के अमेरिका में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। इसमें से काफी हिरासत में लिए गए, कुछ को निर्देशों के साथ रहने दिया गया और बाकी को वापस लौटा दिया गया। 2021–22 में डंकी रूट से जाने वाले भारतीयों की संख्या 63927 थी। 2020–21 में 3662, 2019–20 में 1227, 2018–19 में 8027 लोग डंकी रूट से अमेरिका जाते हुए पकड़े गए। अमेरिकी सीनेट में सीनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने बताया कि

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कुंभ मेले पर अमीरों, कम्पनियों व संघियों का कब्जा

महाकुंभ मेला में अव्यवस्था के बीच हुई भगदड़ व मौतें

हिन्दुत्व एजेण्डा को आगे बढ़ाने और प्रदेश में धार्मिक पर्यटन विकसित करने के इरादे से पिछले साल 23 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के बाद योगी आदित्यनाथ की आरएसएस–भाजपा सरकार ने इस साल कुंभ मेले के आयोजन को लक्षित किया। युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरु हुईं और 'अतिथियों' के स्वागत के लिए देशव्यापी तथा दुनिया भर में प्रचार किया गया। स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार 40 वर्ग किमी क्षेत्र में मेले की सुविधाएं की गयीं। संगम के इर्दगिर्द का क्षेत्र इसका बहुत छोटा अंश है। उम्मीद अनुसार कुल 45 दिन के मेले में 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई गई, जिनमें से 1.5 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। बड़ी संख्या में कारपोरेट घरानों के मालिक, मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य राजनेताओं ने तामझाम के साथ स्नान किया। आकर्षण बढ़ाने के लिए कहा गया कि इस महाकुंभ का अवसर 144 वर्ष बाद आया है, जबकि 2013 का कुंभ मेला भी 144 साल बाद का विशिष्ट आयोजन बताया गया था।

मेले में सफल गोलबंदी की उम्मीद में उत्तरपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द ने जनता के बीच धार्मिक उत्तेजना फैलाने के इरादे से पहले ही घोषित कर दिया था कि मुसलमानों के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए क्योंकि वे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। उनका तर्क था कि ये हमारा तीर्थ है इसमें मुसलमानों का कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी ऐसे धमकी भरे बयान दिये थे।

गरीबों का मेला; अमीरों का अतिक्रमण

हिन्दी भाषी क्षेत्र में, बल्कि गंगा घाटी सभ्यता की तरह विकसित हुई सभी सभ्यताओं में नदियों का खेती के विकास और इस कारण धार्मिक मान्यताओं में एक सम्माननीय स्थान है, जिस वजह से "पाप" धोने के नाम पर बड़ी संख्या में माघ के महीने में हर साल हजारों के संख्या में लोग नदी किनारे एकत्र होकर स्नान करते हैं, जिनमें गंगा जमुना के संगम का विशेष स्थान रहा है। इतिहास और कथाओं का एक बड़ा घालमेल इस व ऐसी सभी परम्पराओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। जहां माघ हर साल मकर संक्रांति से प्रारम्भ हुआ करता है, प्रयागराज में हर 12 साल के बाद (बीच में 6 साल पर अर्धकुंभ) इसे कुंभ का दर्जा (आरएसएस ने इसका अब महाकुंभ नामकरण किया है) मिला हुआ है। इसमें समुद्र मंथन के समय प्राप्त अमृत कलश के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध में कलश से छलके अमृत की बूंद की कथा, राजा हर्षवर्धन द्वारा 12 साल पर प्रयागराज में राजकोष से गरीबों के बीच धन वितरण किया जाना, राजा अकबर द्वारा कुंभ के समय नहान में एकत्र भीड़ देखकर इसे देवस्थान (अल्लाह का स्थान, इलाहाबाद) घोषित करना और अंग्रेजों द्वारा इस मौके पर मेले को ढंग से सजाकर राजस्व वसूली की योजना बनाना, इससे जुड़े है। इस बार का कुंभ वास्तव में बड़ी कम्पनियों, धर्म और राजनीति का संगम है। इस कुंभ में सरकार ने करीब 6000 करोड़ रुपये आबंटित किये जबकि अन्य सहायक आवंटन के साथ 18000 करोड़ रुपये की घोषणा हुई। दुकानों के आवंटन में किराये की भारी–भरकम, पिछले कुंभ से 10 से 15 गुना ज्यादा रकम वसूली गयी।

मेले में गंगा व संगम किनारे कुल उपलब्ध क्षेत्रफल में एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक व्यवस्थाओं (40,000 पुलिस कर्मी वहां रुके, पूरा प्रशासनिक तंत्र स्थापित हुआ), 1.5 लाख टेंट लगे जिनमें 10,000 से 1 लाख रुपये रोज तक का किराया था, 13 अखाड़ों को एकड़ों में जमीन दी गयी और पर्वों पर इन अखाड़ों द्वारा स्नान करने तथा वीआईपी नहान के लिए संगम पर 5 घाट छोड़े गये। आम जन के लिए करीब 35 अलग घाट थे। शहर के अंदर लोगों के प्रवेश को सीमित करने के लिए गंगा किनारे दोनो तरफ विशेष सड़क बनाई गयी और पार करने के लिए 30 पीपा पुल निर्मित किये गये, जिनमें 18 आमजन और शेष विशिष्ट प्रयोग के लिए थे। नहान का सबसे बड़ा पर्व मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को था और उससे 1 दिन पहले व बाद तक शेष सभी पुल बन्द करके जनता की आवाजाही के लिए मात्र 2 पीपा पुल खोले रखे गये।

भीड़ व भगदड़

अच्छी व्यवस्था के भारी–भरकम प्रचार के साथ 13 जनवरी की शुरुआत से शहर में चारो तरफ से भीड़ का आवागमन और मेला क्षेत्र में जमावड़ा शुरु हो गया। 28 जनवरी की भोर 12 बजे से ही भीड़ का दबाव वीआईपी क्षेत्रों व नहान घाटों पर बढ़ता रहा और वीआईपी घाटों पर दबाव छांटने के लिए मेला क्षेत्र कमिश्नर समेत आला अफसरों ने लोगों को संगम पर न जाने और जहां हैं वहीं नहान पूरा करके लौटने की हिदायत दी तथा पुलिस व बैरिकेड द्वारा भीड़ को रोका। मुख्यमंत्री के अनुसार 29 जनवरी को करीब 10 करोड़ लोगों ने आकर नहाना था, जिसकी पर्याप्त व्यवस्था की गयी थी। पर 28 को ही 6 स्थानों पर भगदड़ मची जिस पर उन्होंने लोगों को शांति बनाए रखने और अफवाहों पर विश्वास न करने की हिदायत दी। फिर दिन भर सोशल मीडिया की खबरों के प्रसारण में सैकड़ों लोगों के अलग–अलग घटनाओं में मारे जाने, भगदड़ के वायरल वीडियो द्वारा दिये गये इसके सबूत, सच को दबाने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा लोगों के बिखरे कपड़ों, चप्पलों व अन्य सामान को जेसीबी लोडरों व ट्रैक्टरों से हटाये जाने के वीडियो तथा इनमें लाशों को भी हटाये जाने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश डीजीपी ने शाम को घोषणा की कि संगम किनारे क्षेत्र में 30 लोग मारे गये हैं और कई घायल हैं। लोगों की धार्मिक आस्थाओं का भी बाजारीकरण करने और देश–विदेश के वीवीआईपी लोगों के इंतजाम में मशगूल योगी आदित्यनाथ सरकार 29 जनवरी को अमावस्या के दौरान हुए हादसों को रोक नहीं सकी, बल्कि उसने मृतकों व घायलों की संख्या छुपाने का घोर अमानवीय अपराध किया। पीड़ित परिजनों की मदद और भगदड़ में खो गए लोगों के लिए राहत में भी बदइंतजामी रही। इसको छुपाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने और आरएसएस सोशल मीडिया तथा गोदी मीडिया ने इस तर्क को प्रचारित किया कि घर के छोटे आयोजन में भी कमियां रह जाती हैं, मौतों पर राजनीति न की जाए।

आशीष

शहर का सौन्दर्यीकरण, छोटी दुकानों को उजाड़ा जाना

मेले की तैयारी, एयरपोर्ट से आने जाने के नए पुल व मार्ग, रेलवे स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार, सड़कों के कुछ चौड़ीकरण के साथ अत्यधिक साज–सज्जा के साथ पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभूति कराने की थी। परन्तु इसके लिए बड़ी संख्या में जगह–जगह छोटी दुकानों और ठेले पर व्यवसाय करने वालों को, फल–सब्जी व चाय की दुकानों को बिना वैकल्पिक सुविधा दिये महीनों पहले उजाड़ दिया गया था। सड़क किनारे उनके स्थानों पर बड़े पैमाने पर चित्र व शिल्पकला प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया व बागवानी लगायी गयी। जैसे मेले क्षेत्र में आम जन के लिए खुले आसमान के नीचे ठंड में पनाह लेने की 'व्यवस्था' थी वैसे ही शहर के गरीबों को बड़े पैमाने पर उनके व्यवसाय ठिकानों और कई जगह उनके आवासों पर भी हमला बोला गया है।

भीड़ का अत्यधिक उद्घोष व सरकारी अव्यवस्था

मेले में कितने लोग आते हैं और नहाते हैं, एक लम्बे समय से सरकारों द्वारा सच से बहुत अधिक बेहद विराट आंकड़ों की घोषणा करने की परम्परा रही है। इसकी प्रेरणा बड़े पैमाने पर लोगों का अपने पीछे राजनीतिक समर्थन दिखाना तो रहा ही है, इसमें इतने ज्यादा लोगों के लिए रहने, आने–जाने के परिवहन, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु धन के आवंटन और उसकी मलाई हड़पने का उद्देश्य भी शामिल है, जिसमें बड़ा मीडिया भी भागीदार है। इलाहाबाद शहर की जनसंख्या 15 लाख है। इसकी सड़कों की यातायात क्षमता सुबह और शाम काम के लिए जाने; काम से छूटने और स्कूलों के छूटने के समय लगने वाले जाम के दौरान हर रोज प्रदर्शित है। 28 और 29 जनवरी को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर मार्ग पर पैदल चलने वालों की खचाखच भीड़ कुल 4 किमी से 6 किमी के बीच रही। कुल मिलाकर यह 50 किमी लम्बे दायरे की भीड़ थी और क्योंकि मेला क्षेत्र ठसाठस पैक था। यह केवल छोटी कतारों में आगे बढ़ पा रही थी। क्योंकि इन मार्गों की चौड़ान 10 से 20 मीटर के बीच है, किसी भी आंकलन में यह भीड़ 10 से 12 लाख के दायरे में ही होगी। क्योंकि व्यवस्था में वीआईपी क्षेत्रों को मुक्त रखना था, इसलिए मुख्य संगम क्षेत्र के पीपा पुल बंद थे और उनसे दूर इनके प्रवेश व निकासी की सुविधा थी और प्रशासन ने लोगों को दसियों किमी तक की पदयात्रा कराई।

सरकार और कारपोरेट मडिया के फर्जी दावों को छोड़ दें, तो भी अमावस्या स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग मेला क्षेत्र और शहर के आसपास पहुंच गए थे। जिला प्रशासन का पूरा ध्यान संगम नोज जहां गंगा–जमुना नदियों का मिलन होता है, उस छोटे से स्थान को पूरी तरह से वीआईपी, अखाड़ों और साधु–संतों के लिए आरक्षित करने में लगा रहा। हालांकि सरकारी प्रचार तंत्र में आम जनता को संगम में अमृत स्नान के लिए आमंत्रित किया गया था। इसलिए लाखों लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते थे। 28 –29 जनवरी को कम से कम दो भगदड़ के बाद मेला क्षेत्र और शहर के चारों तरफ की अन्य जिलों से जोड़ने वाली सड़कों को पैदल व वाहनों के प्रवेश के लिए रोक दिया गया।

पैदल क्षेत्र से दूर सड़कों पर वाहनों से आने वाले लोगों को भी रोका गया और इनका जाम सड़कों पर 50 से 100 किमी दूर तक लगा रहा, जिसे खाली होने में कुछ दिन लगे। जो ठसाठस भीड़ में 10–10, 12–12 घंटे तक लोग फंसे थे और इनके फंसे रहने के लिए सरकार ने ढंग से बैरिकेटिंग भी लगा रखी थी और वाहनों में दूर तक फंसे यात्रियों के लिए सरकार ने न तो शौच की व्यवस्था की थी और न ही पीने के पानी व किसी भी तरह के भोजन की। सिर पर भारी गठरी लिए, बगल में बच्चे का हाथ पकड़े बिलखती महिलाएं व बूढ़े इस मेले की अव्यवस्था की स्थायी पहचान बन गये।

पीड़ितों के सहयोग में आम जनता, अल्पसंख्यकों द्वारा दिल खोलकर सहयोग

मुसलमानों समेत सभी लोगों ने दिल खोलकर सहयोग किया। गांव में सभी छोर आम लोगों ने सड़कों पर फंसे यात्रियों के लिए अपने घर–द्वार खोले और उन्हें पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था दी। कई स्थानों पर नौजवानों ने योजनाबद्ध रूप से खिचड़ी व पूड़ी–भाजी बनाकर यात्रियों को खिलाई। 28 जनवरी को भोर से ही फंसे यात्रियों की शौच की आवश्यकता भांपकर एआईकेएमएस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लोगों से सहयोग संगठित कराया और इसकी अपील जारी की।

शहर के इस बहुप्रचारित मेले का सबसे यादगार सहयोग इलाके के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में देखने को मिला। वास्तव में ये इलाके बड़े स्टेशन के किनारे हैं और बड़ी संख्या में इनके बगल के मार्गों से यात्रियों का आना–जाना था। पुलिस ने, शायद इस सोच से कि मुसलमानों की भागीदारी न हो, मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली छोटी–छोटी गलियों पर भी बैरिकेड लगा दिये थे। पर जब भीड़ बढ़ी और लोगों की जरूरतों की पुकार साथ में बढ़ी तो बैरिकेडों की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए और उसी के साथ इन इलाकों में लोगों का आपसी प्यार देखने को मिला। अल्पसंख्यक इलाके में मौजूद मुसलमानों ने, साथ में सिखों ने और हिन्दुओं ने भी अपने घर–द्वार पीड़ित यात्रियों के लिए खोल दिये। जिन मुसलमानों को महामंडलेश्वर और मुख्यमंत्री धर्म भ्रष्ट करने के नाम पर बाधित कर रहे थे, उनकी मस्जिदों, मदरसों, उनके कालेजों व उनके घरों में, महिलाओं और बच्चों ने स्वागत के साथ उन्हें आराम करने की जगह दी, गद्दे व कम्बल दिये, खाना खिलाया और चाय पिलाई। कुछ दिनों के इस प्रयास में शायद आम जन की भागीदारी व जोश किसी भी तरह से रोशनबाग में महीनों चले एनआरसी विरोधी आन्दोलन में भागीदारी से कम नहीं था।

हाल की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय

(सीपीआई (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति ने दिसम्बर 2024 के मध्य में अपनी बैठक में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर एक वक्तव्य को मंजूरी दी। इस वक्तव्य का दूसरा अंश हम

गाजा नरसंहार और मध्य पूर्व में फैलता युद्ध

गाजा में इजरायल का नरसंहार 14 महीने से अधिक समय से जारी है। यह नरसंहार अमेरिकी साम्राज्यवाद के पूर्ण समर्थन से हो रहा है। जबकि जायोनीवादियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है, फिलिस्तीनी ऐसी क्रूरताओं के विरुद्ध एक राष्ट्र के ऐतिहासिक प्रतिरोध की गाथा लिख रहे हैं। उनका जारी प्रतिरोध दिखाता है कि वर्तमान इजरायली सैन्य आक्रमण जैसी गंभीर विपत्ति में दृढ़ संकल्पी लोग कैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक जनमत का समर्थन मिल रहा है। फिलिस्तीनियों ने अपनी लड़ाई अपने हाथों में ले ली है तथा उन्हें लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूथी और इराक तथा सीरिया में प्रतिरोध समूहों का समर्थन मिल रहा है। इन सभी समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है जो मध्य पूर्व में इजरायल का मुख्य विरोधी बनकर उभरा है। अरब शाह फिलिस्तीनियों के समर्थन में ज्यादा कुछ नहीं कर रही, वे अमेरिका–इजराइल का भी खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। हूथियों ने इजरायली बंदरगाहों से आने–जाने वाले जहाजों तथा अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर हमला किया है।

सितंबर 2024 में अमेरिका–इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, जो ताइवान की एक कंपनी द्वारा निर्मित पेजर में माइक्रोबम डालकर पेजर हमलों से शुरू हुआ, फिर भयंकर बमबारी अभियान चला, जिसमें हिजबुल्लाह के नेतृत्व को निशाना बनाया गया और उनमें से कई मारे गए। हजारों नागरिक मारे गए। इजरायल ने लेबनान में जमीनी आक्रमण किया और दक्षिणी लेबनान में सेना भेजी। जमीनी आक्रमण में इजरायल की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और एक महीने में लगभग 150 इजरायली सैनिक मारे गए। उनके हमलावर बल स्वयं हमले का निशाना बन गए, तब इजरायल ने अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौता किया। इस समझौते के अनुसार, इजरायली सेना लेबनान से हट जाएगी और हिजबुल्ला सेना लितानी नदी के उत्तर, सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक हट जाएगी। लेबनान की सेना इजरायल के साथ सीमा को नियंत्रित करेगी। सितंबर 2006 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 में पहले से ही इसका प्रावधान है। इजरायल को इस पर सहमत होना पड़ा, जिससे लेबनान में युद्ध में नुकसान और उस देश में फ्रांस के हितों का पता चलता है।

सीरिया में असद सरकार का पतन

जैसे ही 27 नवंबर को इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ, उसी दिन सीरिया में विद्रोही बलों ने बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। इन बलों का नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) कर रहा है, जिसे पहले अल नुसरा कहा जाता था, जो सीरिया में अल कायदा से संबद्ध रहा है। ग्यारह दिनों में, सीरिया में असद सरकार गिर गई। असद अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ मॉस्को भाग गया और एचटीएस के अंतरिम प्रधानमंत्री ने दमिश्क में सत्ता संभाली। 27 नवंबर की सुबह एचटीएस और अन्य सैन्य समूहों ने इदलिब से पूर्व में अलेप्पो और दक्षिण में होम्स की ओर हमले किए। कथित तौर पर, लड़ाकों के साथ उपकरण और गोला–बारूद ले जाने वाले काफिलों ने 27 की सुबह बाब अल–सलाम पार किया। तीन दिनों के भीतर वे सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में प्रवेश कर गए। एक सप्ताह के भीतर ही वे दक्षिण में हामा और उसके बाद सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होल्म्स में प्रवेश कर गए। ग्यारह दिनों में वे दमिश्क में प्रवेश कर गए।

यद्यपि एचटीएस के नेतृत्व वाले सैन्य समूहों की तेज बढ़त उल्लेखनीय रही, लेकिन अधिक उल्लेखनीय है, सीरियाई सेना और रूस, जिसके सीरिया में सैन्य अड्डे हैं, दोनों की ओर से प्रतिरोध का पूर्ण अभाव। सीरियाई सेना ने कहीं भी प्रतिरोध नहीं किया। असद के मंत्री उग्रवादी संगठनों को सत्ता सौंपने के लिए दमिश्क में ही रहे। यह सीरिया में इन ताकतों के बीच किसी प्रकार के समझौता को दर्शाता है।

हालांकि मुख्य दिशा यही रही है, लेकिन जॉर्डन की सीमा के पास दक्षिण और दक्षिण पूर्व में दारा प्रांत पर कब्जा करने के लिए सैन्य ताकतें उठी। उत्तर और उत्तर पूर्व में अमेरिका समर्थित कुर्द बलों (एसडीएफ) ने डेर अल जौर पर कब्जा लिया और पूर्व से अलेप्पो के बाहरी इलाके तक पहुँच गए।

तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना (एसएनए) और एसडीएफ के बीच उत्तर में झड़पें हुई हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से, एसडीएफ तुर्की सीमा से कुछ दूर मनबिज से पीछे हट गई है जो उत्तरी सीरिया का एक प्रमुख शहर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कुर्द रहते हैं, जिनके एसडीएफ को पीकेके की शाखा के रूप में तुर्की द्वारा आतंकी माना जाता है। अमेरिका ने कथित तौर पर आईएस के खिलाफ इदलिब में हमले शुरू किए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इजरायल लगातार सीरिया पर बमबारी कर उनके हथियार व गोला–बारूद के डिपो और जहाजों को नष्ट कर रहा है। इजरायल ने गोलान पहाड़ियों में विसैन्यीकृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलान हाइट्स को "सदा के लिए" इजरायल का हिस्सा घोषित कर दिया है। 9 और 10 दिसंबर– दो दिनों में इजरायल ने 480 हमले किए। उनका मुख्य उद्देश्य है, इस बदलते समय में सीरिया की सैन्य ताकत को इतना नष्ट कर देना कि कम से कम सैन्य रूप से सीरिया इजरायल का विरोध करने की स्थिति में न रहे। वे आगामी नेतृत्व को अनुकूल नहीं मानते हैं अन्यथा वे उन्हें कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं करते। इजरायल ने घोषणा की है कि वे नए शासकों का मूल्यांकन प्रतिरोध संगठनों के प्रति उनके रवैये के आधार पर करेंगे जिन्हें इजरायल अपना दुश्मन मानता है – ईरान, विरोधी समूह और सर्वोपरि फिलिस्तीनी।

यह स्पष्ट है कि यह स्थिति रूस की मौन स्वीकृति या सहमति के बिना नहीं बनी। एचटीएस ने रूसी सैन्य अड्डों की रक्षा करने की घोषणा की है। दमिश्क में विदेशी मिशन काम कर रहे हैं। रूस सवालों से बचते हुए सीरियाई घटनाक्रम पर अपेक्षाकृत चुप है। जिन परिस्थितियों में बिना किसी विरोध के असद शासन का पतन हुआ वह दर्शाता है की इस स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार थे और कम से कम रूस और तुर्की के बीच एक प्रकार का समझौता, भले ही मजबूरन हुआ हो जिसमें ईरान भी शामिल रहा है।

अमेरिका इसे अपनी जीत के रूप में मना रहा है क्योंकि अमेरिका असद को हटाने के लिए काम कर रहा था। विद्रोहियों को हथियार और पैसे देकर असद को हटाने के अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन करने से लेकर उत्तर–पूर्वी सीरिया में अपने सैनिकों को तैनात करने तक, अमेरिका असद शासन के खिलाफ काम करता रहा है। जिन समूहों को वह इस्लामी आतंकवादी कहता है, उनके प्रति उसका रवैया उसके साम्राज्यवादी हितों से निर्धारित होता है, अपने विरोधियों के खिलाफ अमेरिका उनका समर्थन करता है और अपने सैन्य हस्तक्षेप को उन्हीं के खिलाफ बताकर उचित ठहराता है। हाल में एचटीएस को "उदारवादी" के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। मूल रूप से पूरा "आतंक पर युद्ध" मूलतः उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ और कब्जे के लिए युद्ध है। अमेरिका की दिलचस्पी इस क्षेत्र में रूसी उपस्थिति को कमजोर करने और ईरान को कमजोर करने के लिए मध्य पूर्व में शिया–सुन्नी विभाजन को फिर से भड़काने में थी। यह चीन के खिलाफ भी लक्षित है जिसने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों के सामान्य करने में मध्यस्थता की है।

हालांकि, दो बातें स्पष्ट हैं। सीरिया में इस बदलाव में तुर्किये को फायदा हुआ है जबकि ईरान को नुकसान हुआ है। असद शासन अमेरिका–इजरायल के खिलाफ उसके "प्रतिरोध की धुरी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

तुर्किये को दो तरह से फायदा हुआ है। सबसे पहले, तुर्किये हमेशा से सीरियाई सीमा पर कुर्दों का कब्जा हटाना चाहता था, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा समूह है जो बिना किसी राज्य के एक सटे हुए क्षेत्र में रहते हैं। तुर्किये में सबसे ज्यादा कुर्द हैं जिनकी अलग पहचान को यह नकारता है। तुर्किये सीरिया में कुर्द नियंत्रित किसी भी क्षेत्र को खत्म करना चाहता है जो 2011 के अरब वसंत के बाद उभरा था। इसके लिए, तुर्किये उत्तर और उत्तर पूर्व सीरिया पर नियंत्रण चाहता है। दूसरा, तुर्किये के शासक इस क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं और सीरिया उनका निकट पड़ोसी है।

तुर्किये का फायदा ईरान के लिए नुकसान है। ईरान ने सीरिया में अपनी सैन्य स्थिति बनाए रखी थी और लेबनान के हिज्बुल्लाह को हथियार और गोला–बारूद की आपूर्ति के लिए सीरिया का इस्तेमाल भी किया था। अब यह मार्ग बाधित हो सकता है और यह अमेरिका–इजराइल के लिए फायदेमंद हो सकता है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि नई सीरियाई सरकार के प्रति उनका रवैया इस बात पर निर्भर करेगा कि नई सरकार इजराइल के जायोनी शासकों के प्रति क्या रवैया अपनाती है। सीरियाई विद्रोहियों के बीच अमेरिका–इजरायल के अपने जासूस हो सकते हैं, लेकिन सीरियाई जनता इजरायल की समर्थक नहीं है और गोलान हाइट्स में इजरायल की कार्रवाई से स्थिति और खराब होगी, हालांकि तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है।

इस बार असद सरकार के बने रहने के प्रति रूस की उदासीनता के कई कारण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जिसने इसके संसाधनों को कमजोर कर दिया है। दूसरे, रूस ने कई अरब देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं और इस क्षेत्र में अब उतना अलग–थलग नहीं है, जितना 2015 में था, जब इसने अपनी सेना सीरिया भेजी थी। तीसरे, सीरिया पर तुर्की के साथ उसका घनिष्ठ संबंध रहा है, खासकर अस्ताना प्रक्रिया में। रूस सीरिया के नए शासकों के साथ एक ऐसा तरीका निकालने की उम्मीद कर सकता है, जिन्हें सहयोगियों की आवश्यकता होगी और वे रूस के साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। वास्तव में रूस ने सीरिया में सत्ता में मौजूद समूहों के साथ संपर्क में होने की बात स्वीकार की है। रूस तुर्की और अमेरिका–इजरायल के बीच संघर्ष की अपरिहार्यता पर भी भरोसा कर सकता है, क्योंकि तुर्की का मुख्य लक्ष्य– उत्तर पूर्वी सीरिया को नियंत्रित करने वाला एसडीएफ– अमेरिका द्वारा समर्थित है। रूस के लिए यह क्षेत्र में अपने मुख्य वार्ताकार को ईरान से बदलकर तुर्किये की ओर ले जाने का मामला हो सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि रूस को भी सीरिया में झटका लगा है।

लेकिन सीरियाई सेना के अचानक और कुल पतन के पीछे मुख्य मुद्दे सीरिया के भीतर हैं। 2011 से, असद शासन लगातार विद्रोहियों के साथ युद्ध का सामना करता रहा है। 2015 में रूसी हस्तक्षेप के बाद भी, जिसने असद शासन को स्थिर करने में मदद की, सीरिया का एक बड़ा हिस्सा असद सरकार के नियंत्रण से बाहर रहा। उत्तर–पश्चिम में, इदलिब और अलेप्पो प्रांत का कुछ हिस्सा विद्रोहियों के नियंत्रण में एक डी–एस्केलेशन जोन के रूप में रहा है। इसी तरह का डी–एस्केलेशन जोन दारा प्रांत में है, हालाँकि यह इतना स्वतंत्र नहीं रहा है। उत्तर–पूर्व सीरिया कुर्दों के नियंत्रण में रहा है, जहाँ अमेरिका ने कुर्दों का समर्थन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कुर्द बहुल क्षेत्र में सीरिया का बड़ा तेल संसाधन है और सीरिया राजस्व के इस महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित रहा है। असद शासन की सापेक्ष स्थिरता के दौरान भी, रूस ने उत्तर–पूर्व सीरिया पर कब्जा करने के असद शासन के किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं किया।

घटनाओं पर – 2

सीरिया में पिछले एक साल से आंतरिक हालात बिगड़ते जा रहे थे। बिजली उत्पादन और आपूर्ति बाधित रही है। 20 घंटे तक बिजली कटौती आम बात हो गई है। खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। आम लोग ही नहीं, सेना भी इस आर्थिक तंगी से जूझ रही है। सेना के जवानों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। इससे सेना का मनोबल गिरा है और सेना के जवान भाग रहे हैं। इस खस्ताहाल स्थिति में केवल बल प्रयोग के जरिए शासन चलाना संभव नहीं रह गया है। आम लोगों में असद सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती रही है और उसके सहयोगी उसका समर्थन करने से कतराने लगे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में इजरायल के हमलों का सामना करने में व्यस्त है। ऐसी स्थिति में असद सरकार ने कोई प्रतिरोध न करने का फैसला किया।

विद्रोही ताकतों के तेजी से कब्जे और प्रतिरोध की कमी से संभावित है कि असद सरकार और विद्रोहियों के बीच सत्ता हस्तांतरण पर कुछ सहमति बन गई है। यह बात मंत्रियों द्वारा सत्ता सौंपने और विद्रोहियों, अब सरकार द्वारा सीरियाई सेना के कर्मियों को माफी देने से भी स्पष्ट है। एचटीएस सभी अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान की घोषणा कर रहा है। वैसे भी सीरिया में कई सशस्त्र समूह हैं और उनके बीच संबंधों को ठीक होने में समय लगेगा। सीरियाई लोगों ने हमेशा फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है और नए शासक फिलिस्तीनियों के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाए बिना लंबे समय तक लोगों का समर्थन बनाए नहीं रख सकते।

इस बदलाव को अस्ताना प्रक्रिया के प्रतिभागियों–तुर्किये, रूस और ईरान द्वारा सहायता मिली हो सकती है। तुर्किये ने बार–बार इसका उल्लेख किया है। 7 दिसंबर की शाम को, असद के सीरिया से भागने से एक दिन पहले, तीन अस्ताना प्रतिभागियों ने दोहा में मुलाकात की और केवल सीरिया में शांति और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने का आह्वान किया। जबकि रूस ने बड़े पैमाने पर चुप्पी बनाए रखी है, कुछ ईरानी मीडिया ने असद पर दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया है।

असद सरकार के अचानक पतन ने मध्य पूर्व में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। सीरिया के जुड़ने से मध्य पूर्व संघर्ष और व्यापक हो गया है। सीरिया लंबे समय से प्रमुख साम्राज्यवादी देशों और विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों से जुड़ी क्षेत्रीय शक्तियों का खेल का मैदान रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, जहां इजरायल गाजा में अपने युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है, वे बंधकों को मुक्त करने में सक्षम नहीं हैं, वे लेबनान में फंस गए थे और उन्हें अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत होना पड़ा। संक्षेप में, जायोनी हमलावर नेतन्याहू के पास युद्ध के परिणाम के रूप में दिखाने के लिए और अधिक युद्ध के अलावा कुछ नहीं था। इस स्थिति में, सीरिया के घटनाक्रम का मध्य पूर्व में उभरते परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा जहाँ फिलिस्तीनी जायोनी कब्जेदार के खिलाफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका संघर्ष आकार ले रहा है और मध्य पूर्व में कथा को आकार देना जारी रखेगा।

दुनिया में जारी युद्ध

दुनिया में 40 से अधिक देशों में सक्रिय संघर्ष (युद्ध) चल रहे हैं। इनमें से कई युद्ध क्षेत्र, हताहतों की संख्या के मामले में बड़े हैं और इनका भू–राजनीतिक प्रभाव व्यापक है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध, म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रतिरोध का युद्ध ऐसे ही उदाहरण हैं। जैसा कि राजनैतिक प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है, विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और संघर्ष में परमाणु हथियार शक्तियों के शामिल होने से परमाणु युद्ध का खतरा भी फिर से सामने आया है।

अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोध के बढ़ने के साथ ही साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित देशों के बीच अंतर्विरोध भी अधिक गंभीर तरीके से व्यक्त हो रहा है। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सभी पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें अफ्रीका में बढ़ते अलगाव का सामना कर रही हैं। दूसरी ओर, ब्रिक्स (BRICS) विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। सितंबर में कजान में ब्रिक्स ने एक सफल शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और मिस्र शामिल हुए। इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जबकि संवाद भागीदारों के रूप में देशों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ब्रिक्स जी–7 जितना एकजुट समूह नहीं है, लेकिन इसका उभरना महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देकर और विनिमय मुद्रा के रूप में डॉलर के उनयोग को कम करके डी–डॉलरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर आमादा है। राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्प ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि यदि वे कोई वैकल्पिक मुद्रा जारी करते हैं तो उनके अमरिका में आयातित सामान पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, एक ऐसी धमकी जिसका आज दुनिया में आर्थिक संबंधों की वास्तविकता को देखते हुए बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

गहराता संकट, जनता पर बढ़ता बोझ और मजदूर वर्ग पर हमले, साम्राज्यवाद के बीच बढ़ता अंतर्विरोध, ये सभी स्थितियां जनसंघर्षों के विकास के लिए अनुकूल बना रही हैं। हालांकि, क्रांतिकारी ताकतें कमजोर बनी हुई हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि आंदोलन के विकास के लिए इस अनुकूल स्थिति का उपयोग करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

(अंग्रती से अनुदित।

इसका पहला अंश प्रतिरोध के पिछले अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। इसका अगला भाग पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।)

गहन है अंधकारा... सब दांव पर लगा विदेश भाग रहे युवा

(पृष्ठ 2 का शेष)

करीब 45000 भारतीयों को दक्षिणी सीमा पर पकड़ा गया था। डंकी शब्द का अर्थ गधे से ही है, लेकिन यह एक पंजाबी मुहावरे से निकला शब्द है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना।

दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भारत इसलिए सबसे ज्यादा निराशा के गर्त में है, क्योंकि भारत के कुल बेरोजगारों में 80 प्रतिशत युवा हैं। यह तथ्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने मार्च 2024 में अपने एक रिपोर्ट के हवाले से दी थी। द इंडिया अपॉइंटमेंट रिपोर्ट 2024 बताती है की 20 वर्षों से भारत के युवाओं में बेरोजगारी लगभग 30 प्रतिशत बढ़ चुकी है। वर्ष 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.02 प्रतिशत थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आईसीडी की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है। बेरोजगारी में ग्रेजुएट महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। 2022 में ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी, जो ना तो नौकरी कर रही थीं और ना ही किसी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रही थीं। ऐसी महिलाओं की संख्या 48.4 प्रतिशत थी, जबकि पुरुष बेरोजगार 9.8 प्रतिशत थे। इस तरह महिलाओं में लगभग 95 प्रतिशत की बेरोजगारी थी।

देश में सरकारी नौकरियां कम हैं। इसलिए रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र में है या फिर लोग अपना काम करते हैं। वर्ष 2002 से 2022 के बीच औपचारिक नौकरी कर रहे लोगों की संख्या मात्र 10 प्रतिशत थी, जबकि 90 प्रतिशत लोग या तो अपना काम कर रहे थे या अनौपचारिक रोजगार में थे। वर्ष 2000 के बाद से औपचारिक रोजगार का अनुपात जो बढ़ रहा था उसमें 2018 के बाद तेजी से गिरावट आई और ठेका आधारित नौकरियों में भारी वृद्धि हुई है, जबकि बहुत कम लोग नियमित और लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब में हैं। नौकरी पेशा लोगों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, जिन्हें लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यही नहीं स्थाई नौकरी पेशा लोगों के वेतन में 2019 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है या बहुत कम हुई है। 2012 से 2022 के बीच अनौपचारिक रोजगार करने वालों की आय में मामूली वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि लाखों लाख रुपया खर्च करके और जान हथेली पर लेकर विदेश जाने के लिए मध्यम वर्ग क्यों लालायित है, क्योंकि स्वरोजगार के लिए भी यहां मार्केट नहीं बची है, खरीदार नहीं है और उनकी कोई आय नहीं है या बहुत ही मामूली आय है, जो जीवन यापन के लिए है। दिसंबर 2024 में सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी के अनुसार बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर 2024 में घटकर 8 प्रतिशत रह गई। इस दौरान बेरोजगारों की संख्या में 34 लाख की गिरावट देखने को मिली, जबकि रोजगार सिर्फ 5 लाख लोगों को ही मिला। इसका मतलब है कि 29 लाख लोगों ने रोजगार पाने का प्रयास ही छोड़ दिया। अर्थात वह रोजगार तलाश की मार्केट से ही बाहर हो गए।

देश में बेरोजगारी शिक्षित तबके की ही नहीं, बल्कि अशिक्षित और मजदूरी के काम के लिए भी स्थिति भयावह है। इजरायल–फिलिस्तीन और रूस–यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय श्रमिक युद्धरत देशों में भी काम करने के लिए गये हैं। इजराइल ने भारत से कुछ हजार श्रमिक, निर्माण क्षेत्र के लिए मजदूरों–मिस्त्रियों की मांग की, तो उत्तर प्रदेश में हजारों मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गए, जिसमें से 10000 लोग वहां भेजे गए। यह तो सरकारी स्तर पर था, लेकिन अच्छी नौकरी की तलाश में स्वतः रुस गए लोगों को पुतिन सरकार ने सैनिक बना कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया। वहां कई भारतीय मारे गए। ऐसे भारतीयों की संख्या कभी सरकार ने नहीं बताई। इजरायल में निर्माण कार्य के लिए गए लोगों का वेतन एक से डेढ़ लाख रुपये मासिक बताया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में इन मजदूरों को 10000 की भी मजदूरी प्रति माह नहीं मिल पाती। अपने परिवार की बेहतरी के लिए यह मजदूर जान हथेली पर लेकर भी पूरी दुनिया में सस्ते श्रमिक के रूप में काम करने पहुंच रहे हैं।

यह किसी भी स्वतंत्र, स्वायत्त, लोकतांत्रिक और स्वाभिमानी देश के लिए शर्मनाक है, लेकिन आरएसएस–भाजपा की बेशर्म सरकार देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनाने का दिवास्वप्न दिखा रही है। इसके विपरीत वह लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग कर नौकरशाही के जरिए जनता के बुनियादी सवालों को कुचल रही है। लोगों की सरल धार्मिक भावनाओं को सांप्रदायिक उन्माद में बदल कर अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और लोकतंत्र व अमन पसंद लोगों के खिलाफ खड़ा कर फासिस्ट सत्ता की ओर कदम बढ़ा रही है।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आंदोलन की घोषणा

संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा (एनपीएफएएम) को तीन काले कृषि कानूनों का प्रतिरूप और किसान विरोधी बताते हुए अखिल भारतीय आंदोलन की चेतावनी दी है। नई दिल्ली में 24–25 जनवरी को आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) की बैठक में किसान विरोधी, संघवाद विरोधी, राष्ट्र विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक एनपीएफएएम को तत्काल निरस्त करने, कानूनी रूप से गारंटी कृत खरीद के साथ एमएसपी/सी2+ 50% देने, कर्ज मुक्ति सहित किसानों की अन्य लंबित मांगों पर संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया है। किसान नेताओं ने कहा है कि इन मांगों को आज तक एनडीए–3 सरकार स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं है।

24 जनवरी को दिल्ली में एसकेएम की आमसभा में कई राज्यों के किसान संगठन शामिल हुए और नेताओं ने अपनी राय रखी कि मोदी सरकार कॉरपोरेट एकाधिकार के कड़े शिकंजे में है, वह किसानों की मांगों का सम्मान नहीं करती है तथा एनपीएफएएम या अन्य कॉरपोरेट समर्थक सुधारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अतः इन सभी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए एक बड़े मजबूत और देशव्यापी संघर्ष की योजना बनानी होगी, जो भागीदारी और जुझारूपन में 2020–21 को दिल्ली बॉर्डर पर आयोजित ऐतिहासिक किसान संघर्ष से भी ज्यादा व्यापक हो।

किसान नेताओं के अनुसार इस तरह के शक्तिशाली देशव्यापी जन आंदोलन के निर्माण के लिए दो पूर्व अपेक्षित कारक हैं: किसानों के बीच मुद्दा आधारित एकता और देश भर में गांव–कस्बों के स्तर तक मजदूर किसान एकता को बनाना और उसका विस्तार जरूरी है। इसलिए महासभा ने एसकेएम की छह सदस्यीय समिति को एसकेएम (एनपी) व केएमएम के साथ संयुक्त और समन्वित कार्रवाई के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने का और एनपीएफएएम के मुद्दे सहित अन्य मुद्दा आधारित एकता बनाने का निर्देश देने का फैसला किया है। इसके अलावा सभी संगठनों के साथ 12 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में एक समन्वय बैठक आयोजित करने का भी फैसला किसान संगठनों ने किया है। एसकेएम श्रमिकों और अन्य सामाजिक समूहों के साथ भी व्यापक एकता बनाने के लिए प्रयास करेगा।

किसान नेताओं ने बैठक में कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनपीएफएएम के कॉरपोरेट समर्थक एजेंडे को वापस नहीं लेने पर अड़े रहते हैं, तो अगले 3 महीनों के भीतर किसान अखिल भारतीय ग्रामीण हड़ताल करके संघर्ष को और तेज करेंगे। एसकेएम सभी कारपोरेट विरोधी तबकों से किसानों के संघर्ष का समर्थन करने के लिए आगे आने की अपील करता है।

एसकेएम ने किसानों से आह्वान किया है कि वह 76 वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को जिला और उपमंडल स्तर पर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों के साथ बड़े पैमाने पर मार्च निकालें, जिसमें चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने सहित उपरोक्त मांगे शामिल हों। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने किसानों की परेड को समर्थन दिया है और कार्यकर्ता अपने वाहनों के साथ इसमें शामिल होंगे। ज्ञात हो की 26 जनवरी को पंजाब व हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों के अनेक जिलों में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली और मार्च निकाले।

एनसीसी ने 8 और 9 फरवरी 2025 अथवा किसी अन्य तारीख को संसद के सभी सदस्यों के आवासों व कार्यालयों पर सामूहिक प्रतिनियुक्ति कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें कॉरपोरेट समर्थक सुधारों के कारण सभी कामकाजी लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव की गंभीरता के बारे में समझाया जा सके और उनसे प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी वास्तविक मांगों को रखकर किसानों का समर्थन करने की अपील की जा सके।

एसकेएम की सभी राज्य समन्वय समितियां जल्द से जल्द बैठक करेंगी और संघर्ष के अगले चरण की योजना बनाएंगी, जिसका उद्देश्य 5 मार्च 2025 से राज्यों, केंद्र, जिला और उपमंडल स्तर पर 'पक्का मोर्चा' अर्थात निरंतर धरना व प्रदर्शन शुरू करना है। राज्य एनसीसी प्रतिनिधिमंडल संबंधित मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और उन्हें अपने राज्य विधान सभा सत्रों में एनपीएफएएम को

(शेष पृष्ठ 7 पर)

वरिष्ठ क्रांतिकारी नेता का. धर्मन्ना 12 जनवरी 2001 को पुलिस के हाथों शहीद हो गये थे। उनकी शहादत के दिन 12 जनवरी को इस वर्ष उनको श्रद्धांजलि देते हुए सी.पी.आई. (एम–एल) न्यू डेमोक्रेसी के कार्यकर्त्ता। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में किया गया।

विजयवाड़ा : टीडीपी सरकार के खिलाफ आटो चालकों का विरोध प्रदर्शन

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑटो चालकों और कर्मचारियों ने प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के 8 महीने बाद भी चुनावों के दौरान किए गए किसी भी वायदे को पूरा न करने के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। टीडीपी सरकार के रवैए से आक्रोशित ऑटो कर्मचारियों ने रविवार 12 जनवरी को विजयवाड़ा में इफ्टू से सम्बंधित प्रगतिशील ऑटो कार्मिक संघम के नेतृत्व में 250 ऑटो चालकों के साथ एक प्रदर्शन किया। सिथन्नापेट गेट सेंटर से बीआरटीएस रोड पर फूड कोर्ट जंक्शन तक आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव के दौरान टीडीपी द्वारा परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों से किए गए वायदों को लागू करने की मांग करते हुए जोरदार नारे लगाए। इस अवसर सभा को संबोधित करते हुए प्रगतिशील ऑटो कार्मिक संगम के अध्यक्ष डी श्रीनिवास राव ने याद दिलाया कि चुनाव के दौरान टीडीपी और उसके गठबंधन दलों ने वोट के लिए कई बातें और आश्वासन दिए थे। उन्होंने वायदा किया था कि ऑटो और मोटर कर्मचारियों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और बोर्ड के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, विवाह और बीमारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी।

डी श्रीनिवास राव ने कहा कि इसी तरह टीडीपी ने चुनाव प्रचार माध्यमों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था कि मोटर कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने वाले जिओ नंबर 21 को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य वायदे किए गए थे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के 8 महीने बाद भी सरकार का एक भी वायदा पूरा ना करना मोटर कर्मचारियों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा यह खेद जनक है कि राज्य सरकार जनता के गुस्से का सामना करने के बावजूद अपने वायदों को लागू करने के लिए आगे नहीं आई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ऑटो और मोटर कर्मचारियों से किए गए उपरोक्त चुनावी वायदों को तुरंत लागू नहीं करती है, तो वह पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे।

इफ्टू के राज्य महासचिव के. पोलारी ने कहा कि जब वे विपक्ष में थे तब टीडीपी और और उसके सहयोगी दल मूल्य वृद्धि, पेट्रोल–डीजल और गैस की दरों पर चिंता जताते थे और आज सत्ता में आने के बाद वह अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। चूंकि टीडीपी केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है इसलिए श्रमिकों की मांग है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें कम की जाएं और उन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार ईमानदारी से ऑटो और मोटर श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना करे। जुर्माने के जिओ नंबर 21 को रद्द करे और प्रत्येक मोटर श्रमिकों को रु. 15000 दे। इसके अलावा नए ऑटो खरीदने के लिए 5 प्रतिशत के ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराए। उन्होंने बताया कि अगर टीडीपी गठबंधन सरकार द्वारा किए गए वायदों को तुरंत लागू नहीं किया गया, तो वह पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में इफ्टू के जिला अध्यक्ष मुनि शंकर, प्रगतिशील ऑटो यूनियन के महासचिव सीएच पेद्धिराजू, नेता डी श्रीधर बाबू, वाई अप्पा राव, पिंगली रमाना और रफी सहित कई अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए।

प्रवासी भारतीय युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार की छात्र तथा युवा संगठनों द्वारा निंदा

प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडैंट्स यूनियन (पी.डी.एस.यू.), पंजाब स्टूडैंट्स यूनियन (पी.एस.यू.), नौजवान भारत सभा तथा प्रोग्रेसिव यूथ लीग ने अमेरिका की ट्रम्प सरकार द्वारा अमेरिका से भारत वापस भेजते समय भारतीय युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार तथा इस पर भारत सरकार की चुप्पी की तीव्र आलोचना की है तथा इसे सरकार की साम्राज्यवादी ताकत के सामने दब्बू नीति बताया है।

छात्र तथा युवा संगठनों ने कहा है कि भारतीय युवाओं के देश से पलायन के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। देश में उचित रोजगार न मिलने के कारण भारतीय युवा किसी भी तरीके से विदेश जाने को मजबूर होते हैं तथा इसमें उनके परिवारो को काफी खर्च करना पड़ता है।

छात्र तथा युवा संगठनों ने मांग की है कि भारत सरकार अमेरिका से लौटे युवाओं के परिवारों को हुए वित्तीय नुकसान की पूरी भरपाई के लिए वित्तीय सहायता दे, क्योंकि इस प्रकार का पलायन सरकार की विफलता के कारण होता है। संगठनों ने मांग की कि निर्वासितों को लेकर आने वाले किसी भी अमेरिकी विमान को उतरने की अनुमति भारत सरकार न दे जब तक उन्हें मानवीय और सम्मानजनक तरीके से न लाया जाये।

काम के घंटे बढ़ाने पर इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी का बयान

● एल एंड टी के चेयरमैन द्वारा 90 घंटे-7 दिन के कार्यसप्ताह की वकालत की इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी निंदा करती है!

● इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी इस मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के श्रम मंत्रियों एवं केंद्र सरकार की चुप्पी की निंदा करती है!

● इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी मजदूर वर्ग से आह्वान करती है कि - चार लेबर कोड को निरस्त करने के लिए संघर्ष तेज करें!

इंग्लैंड में 1800 के शुरुआती दशकों में मजदूरों की स्थिति का वर्णन, जिसमें उस समय के फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट शामिल हैं, मजदूरों की शुरुआती स्थितियों का जीवंत विवरण देती हैं, जहां मजदूर तब तक काम करते हैं जब तक वे बेहोश होकर गिर नहीं जाते, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता और उनकी जगह किसी और को रखा जाता। दिलचस्प बात यह है कि उन वर्षों में भी, एक दिन (रविवार) को आराम के दिन के रूप में सम्मान दिया जाता था।

यह मजदूर वर्ग का आंदोलन ही था जिसने 18 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 10 घंटे और अंततः 8 घंटे के कार्य दिवस की स्थापना की – 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जीने और मनोरंजन के लिए।

दुनिया भर में मजदूर आंदोलन के कमजोर होने के कारण कॉरपोरेट जगत ने 8 घंटे के कार्यदिवस के अधिकार पर हमला किया है। एलन मस्क, जैक मा और अन्य लोगों ने हमले शुरू किए हैं।

अधिकतम मुनाफे की इस बेलगाम भूख को दर्शाते हुए, अक्टूबर 2023 में इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति ने एक बयान दिया, जिसमें युवाओं से सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आह्वान किया गया। यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा 8 घंटे के कार्यदिवस के अधिकार पर चल रहे ठोस हमले के अनुरूप था, जिसे कोरोना लॉकडाउन की आड़ में संसद के माध्यम से 4 लेबर कोड के रूप में पारित किया गया था। कई राज्यों में काम के घंटे बढ़ाने की घोषणा की गई, जबकि लचीले काम के घंटों को आगे बढ़ाने के प्रयासों को कुछ क्षेत्रों के मजदूरों ने रोक दिया। आज तक मजदूर वर्ग के प्रतिरोध ने 4 लेबर कोड को अमल में आने से रोक रखा है।

अब, जबकि हमारे मजदूरों के अबाधित कॉरपोरेट (मुख्यतः विदेशी) शोषण की मददगार भारत की केंद्रीय सरकार, 4 लेबर कोड लागू कराने के लिए नए सिरे से जोर दे रही है, लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन का बयान आता है – कोई छुट्टी नहीं, 90 घंटे प्रति सप्ताह या लगभग 13 घंटे प्रतिदिन काम। ये प्रस्ताव युवाओं की क्षमताओं की तारीफ, ''राष्ट्र की जरूरतों'' की अपरिहार्यता और 'चीन के बराबरी करने' की छद्म राष्ट्रवादी भावनाओं के चोगे में लपेटकर दिया गया हैं। इसमें घटिया और पितृसत्तात्मक, उपहास भी है – ''आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक देख सकते हैं!''– एक ऐसे देश में जहां महिलाएं हर क्षेत्र में काम करती हैं, एक ऐसे युग में जहां विविध मनोरंजन उपलब्ध हैं जिन्हें मजदूरों की पहुंच में लाया जाना चाहिए और एक ऐसे युग में जहां मनोरंजन के साधनों का असीमित इस्तेमाल संभव है। मजदूर वर्ग के पारिवारिक जीवन के अधिकार का, दुनिया के अमीरों के लिए अधिकतम मुनाफा पैदा करने के अलावा अन्य इच्छाएं होने का उपहास– यही लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन का एजेंडा है। टिप्पणीकारों ने सही कहा है कि एल एंड टी जैसी कंपनियों के चेयरमैन अपने मजदूरों के औसत वेतन से लगभग 500 गुना कमाते हैं, और अन्य लाभ अलग से प्राप्त करते हैं। ''भारतीय'' बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाने वाली एलएंडटी में पोर्टफोलियो फंड, प्रत्यक्ष निवेश और म्यूचुअल फंड के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश है।

सभी आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा अत्यधिक काम के खिलाफ चेतावनी देते हैं। पिछले अक्टूबर में, भारत में आईटी क्षेत्र में एक युवा कुशल महिला कर्मचारी, जो मुश्किल से अपनी किशोरावस्था से बाहर निकली थी, अत्यधिक काम के कारण मर गई। लेकिन कॉरपोरेट कब मजदूरों और कर्मचारियों को इंसान के रूप में देखते हैं?

इस कथन का कॉरपोरेट भारत के विभिन्न सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया है क्योंकि वे एक ही नस्ल के हैं। इससे पहले, 70 घंटे के सप्ताह के घृणित विचार को सही ठहराने के लिए, नारायण मूर्ति ने झूठे दावे किए थे कि जर्मनी और जापान जैसे देशों में विस्तारित कार्य घंटों ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया है। वास्तव में ऐसे कई देशों में पिछले कुछ वर्षों में काम के घंटों में लगातार गिरावट आई है। जर्मनी में यह सप्ताह में 28 घंटे है जबकि जापान में 1961 में 44 घंटे थे जो 2017 में घटकर 35 घंटे हो गए। इसलिए यह कहना कि काम के घंटे बढ़ाने से प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी, एक उथला तर्क है।

वास्तव में, दुनिया की विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विकासशील या पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काम के घंटे कम हैं। हमारे देश में, निर्माण स्थलों पर ठेके या आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले युवा, मेट्रो रेल पुल और पटरियाँ बिछाने वाले और कुछ विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले मामूली वेतन पर दस से बारह घंटे से अधिक काम करते हैं जबकि कानूनी काम के घंटे आठ हैं।

आठ घंटे के कार्य दिवस को कानूनी रूप देने के पीछे दुनिया भर के मजदूरों के बलिदानों का एक बड़ा इतिहास है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपने कन्वेंशन नंबर 1 में स्पष्ट रूप से कहता है कि औसत कार्य दिवस 8 घंटे का होना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेट लचीले कार्य घंटों के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार 4 लेबर कोड के द्वारा इसका अनुपालन कर रही है।

मोदी सरकार 4 लेबर कोड को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जो प्रभावी रूप से मजदूरों के अधिकारों और 8 घंटे के कार्य दिवस का उल्लंघन करते हैं। भारत में मजदूरों के कई तबकों के लिए 12 घंटे का कार्य दिवस एक वास्तविकता है क्योंकि राज्य सरकारों और निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों को लागू करना छोड़ दिया गया है। अब केंद्र ने घोषणा की है कि वह मार्च 2025 से लेबर कोड़ों को लागू करना चाहता है। और साथ ही सुब्रमण्यम का किसी भी अधिकार के खिलाफ बेशर्म बयान सामने आता है। वास्तव में लगातार बढ़ते कार्य घंटों का सिद्धांत मजदूरों की शीघ्र मौत का आह्वान है, जिनके जीवन को व्यर्थ माना जाता है। यह बहुत शर्म की बात है कि देश के श्रम मंत्री ने इस बयान के खिलाफ बोलने की जहमत नहीं उठाई। मौन का मतलब है सहमति। लचीले काम के घंटे और बिना अवकाश के काम करना मजदूरों के जीवन के लिए मौत की घंटी है!

वास्तव में, भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है और केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकारों द्वारा भी रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लचीले काम के घंटे केवल बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं और यह एक खराब नीति है। भारत के लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि सरकार लोगों की जरूरतों या भलाई के बारे में कितनी कम परवाह करती है।

इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटीः

- एल एंड टी चेयरमैन के बयान की कड़ी निंदा करती है।
- मांग करती है कि भारत के श्रम मंत्री इस मजदूर विरोधी बयान की कड़ी निंदा करें।
- मजदूर वर्ग से आह्वान करती है कि वे 4 लेबर कोड को निरस्त करने तथा श्रम कानूनों के अमल के लिए संघर्ष को तेज करें।
- सभी स्तरों पर सभी ट्रेड यूनियनों से आह्वान करती है कि वे 4 लेबर कोड को निरस्त करने तथा श्रम कानूनों के अमल के लिए सामूहिक लड़ाई को मजबूत करें।'
- मांग करती है कि सभी राज्य सरकारें, खासकर गैर एनडीए सरकारें, विधानसभाओं में 4 लेबर कोड को निरस्त करने के प्रस्ताव पारित करें तथा मजदूर विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक लेबर कोड़ों के लिए उन्होंने जो नियम बनाए हों उन्हें रद्द करें।

(इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी द्वारा 12 जनवरी 2025 को जारी)

सासाराम: रंगदारी के खिलाफ व सुविधाओं के लिए आटो-रिक्शा चालकों का सम्मेलन

ऑटो–रिक्शा चालकों का शोषण और उत्पीड़न नगर निगम, पुलिस और रंगदारी टैक्स के कारण बढ़ता जा रहा है, जबकि उनके लिए स्टैंड, पानी व शौचालय आदि की कोई सुविधा नगर निगम और जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं कराता। ऑटो–रिक्शा चालकों की समस्याओं पर ध्यान न दिये जाने के विरोध में सासाराम के कुशवाहा सभागार भवन में 19 जनवरी 2025 को एकदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चालकों की समस्याओं के समाधान की जोरदार मांग की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने जिला प्रशासन से समस्याओं के समाधान की मांग की है अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शहर के कुशवाहा सभागार में रविवार को आयोजित ऑटो–रिक्शा चालकों के सम्मेलन की अध्यक्षता जनवादी ऑटो–ई रिक्शा चालक मजदूर संघ के अध्यक्ष दिलशेर बेग और संचालन महेंद्र सिंह यादव ने किया।

सभा में वक्ताओं ने नियमों के विरुद्ध नगर निगम के ठेकेदारों के द्वारा जहां–तहां ऑटो और ई रिक्शा चालकों से दैनिक टैक्स वसूली, ऑटो स्टैंड पर अतिक्रमण और शहर में ट्रैफिक पुलिस राज सहित अन्य मांगों को लेकर चिंता प्रकट की और प्रशासन से मांग की है कि वह इन समस्याओं का समाधान करे। एक दिवसीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए संघ के सचिव संजय शर्मा ने कहा कि शहर में जिस तरह से ऑटो स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाती, लेकिन दैनिक टैक्स की वसूली नियमित होती है, जो सरासर गलत है। वक्ताओं ने कहा कि पहले शहर में ऑटो स्टैंड की व्यवस्था हो। उसमें परिचालकों के बैठने पानी व शौचालय आदि की भी सुविधाएं हों, इसके बाद ही टैक्स की वसूली होनी चाहिए। वक्ताओं ने इस पर सबसे ज्यादा आक्रोश व्यक्त किया कि ऑटो चालक नगर निगम को टैक्स देते हैं परंतु इसके बावजूद रंगदारी टैक्स वसूला जाता है। पुलिस भी अवैध वसूली में पीछे नहीं रहती और इस तरह का शोषण उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस पर नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी विचार करना चाहिए, नहीं तो ऑटो–रिक्शा चालक बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ेंगे। सभा में विजय पासवान, एआईकेएमएस के जिला सचिव अयोध्या राम, राजेंद्र सिंह यादव, अमृतेश भगत, मनोज पासवान, सुनील यादव, ज्वाला प्रसाद, अजीत कुमार, भगेलू पासवान, भगवान सिंह, भगवान शर्मा, मकसूद खान, ज्वाला प्रसाद और दिनेश कुमार आदि नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आंदोलन की घोषणा

(पृष्ठ 6 का शेष)

अस्वीकार करने का प्रस्ताव अपनाने के लिए राजी करेगा और केंद्र सरकार से इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की भी अपील करेगा। संघर्ष के इस चरण का स्वरूप और समय संबंधित राज्य समन्वय समितियों द्वारा तय किया जाएगा। एसकेएम सभी राजनीतिक दलों के साथ समन्वय करेगा और उन्हें किसानों की लंबित मांगों पर नई दिल्ली में बैठक करके चर्चा के लिए आमंत्रित करेगा। साथ ही मेहनतकश लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए आगामी सभी विरोध कार्यों के लिए उनका समर्थन सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा।

(यहां एस.के.एम. द्वारा जारी वक्तव्य का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है।)

गाजा युद्ध विरामः प्रतिरोध की विजय

इजराइल सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति के बाद इजरायल और फिलीस्तीन प्रतिरोध समूह के बीच युद्ध विराम 19 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। यह फिलिस्तीन के लोगों की जीत है, जो पिछले 15 महीनों से भी ज्यादा समय से लगातार बमबारी और हत्याओं का सामना कर रहे हैं। बीते 15 महीनों में गाजा में 47000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और लगभग 110000 लोग घायल हुए हैं। इजरायल सरकार को युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसका मुख्य कारण फिलिस्तीनी लोगों का धीरज, जियोनिस्ट हमलावरों और कब्जेदारों के खिलाफ उनके प्रतिरोध की महान भावना है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता से 15 जनवरी को दोहा में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। युद्ध विराम समझौते पर इजराइल, फिलिस्तीनी प्रतिरोध की ओर से हमस, कतर और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। फिलिस्तीनी पक्ष की ओर से हमस के अलावा पीएफएलपी और इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियों ने भी युद्ध विराम वार्ता में भाग लिया था।

यह फिलिस्तीन लोगों के प्रतिरोध की जीत है, यह इस तथ्य से भी पूरी तरह साबित होता है कि जिस इसराइल सरकार ने गाजा से हमास को खत्म करने की कसम खाई थी, उसे उसी हमस के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। युद्ध विराम समझौते में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा से इजरायली सशस्त्र बलों की वापसी और गाजा को मानवीय सहायता की आपूर्ति का प्रावधान है। इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और इजरायली सशस्त्र बलों की वापसी गाजा में आबादी वाले केंद्रों से इजरायली सशस्त्र बलों की वापसी के चरणबद्ध तरीके से होनी है।

युद्ध विराम समझौते का फिलिस्तीन लोगों और फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समर्थन करने वालों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। वास्तव में फिलीस्तीन समूह, उनके समर्थकों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारी बहुमत सहित विश्व के लोगों द्वारा लगातार युद्ध विराम की मांग की जाती रही है, लेकिन इजरायल द्वारा बार–बार और हठपूर्वक इसका विरोध किया जाता रहा है। इजरायल ने अब जो नरमी दिखाई है वह काफी हद तक फिलिस्तीनी लोगों के लगातार वीरतापूर्ण प्रतिरोध, अरब देशों में प्रतिरोध समूहों द्वारा भारी दबाव, इसराइल सरकार के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे व्यापक विरोध के कारण है। अमेरिकी साम्राज्यवादी समर्थकों द्वारा सैन्य अभियानों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की असंभवता भी वजह है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिकंन ने स्वीकार किया कि इसराइल जितने फिलिस्तीनों को मार पा रहा है, हमस को प्रतिरोध के लिए उससे ज्यादा लोग मिलते जा रहे हैं।

फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी युद्ध ने इजरायली सामाजिक और राजनीतिक जीवन में संकट को और गहरा कर दिया है। इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पार्टी को युद्ध के कारण इजरायल के अंदर बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हिजबुल्ला के साथ लगातार गोलीबारी (लेबनान में युद्ध विराम से पहले) के कारण इजरायल के लोगों को उत्तरी इजराइल में सीमावर्ती क्षेत्र के बड़े हिस्से को खाली करना पड़ रहा था। इजराइल ना केवल गहराते आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, बल्कि ऐसी रिपोर्टें भी आ रही थीं कि 2 लाख से ज्यादा इजरायली नागरिक जिनके पास दोहरी नागरिकता है और जिनमें से कई पेशेवर और योग्य व्यक्ति शामिल हैं, देश छोड़ रहे हैं। इस स्थिति ने नेतन्याहू सरकार को अपने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कुछ अतिवादी दलों के विरोध के बावजूद झुकने के लिए मजबूर कर दिया था।

इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ दुनिया भर में जनता के बढ़ते विरोध, जिसका उल्लेख अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भी किया है, जिसमें अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी शामिल हैं, ने अमेरिकी सरकार को युद्ध विराम के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी आधिकारिक अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ युद्ध विराम वार्ता में भाग लिया। युद्ध की बढ़ती लागत जिसका मुख्य बोझ अमेरिका पर था, प्रतिरोध को समाप्त कर पाने की असंभवता, अरब जनता के बीच बढ़ते अलगाव, यहां तक की विनम्र अरब शासक भी अब उनका खुलकर साथ देने को तैयार नहीं थे, ने अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों विशेष रूप से चीन को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर दिया, जिसने इस नरसंहारक युद्ध के मुख्य समर्थक अमेरिकी प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

फिलिस्तीन के बाहर प्रतिरोध समूहों द्वारा झेले गए कुछ झटकों के बावजूद इस युद्ध विराम पर सहमति बनी है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के कारण हिज्बुल्लाह को भी कुछ नुकसान हुआ है और ईरान के प्रभाव में कमी आई है। हालांकि हूतियों के नेतृत्व वाले यमन ने अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल द्वारा लगातार बमबारी के बावजूद अपना प्रतिरोध जारी रखा है। जहां अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों ने प्रतिरोध समूहों के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया है, ईरान का सवाल अलग है। ईरान ने रूस के साथ 20 साल का समझौता किया है, जिसमें रक्षा सहयोग भी शामिल है।

युद्ध विराम से अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित नरसंहारकारी जायोनी शासन के अत्याचारों का अंत नहीं होगा और ना ही फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ फिलिस्तीन की जमीन को हड़पने और इस विनाश के युद्ध के जरिए फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से पूरी तरह बेदखल करने की उनकी साजिशों का अंत होगा। इसलिए फिलिस्तीनियों और उनके उद्देश्यों का समर्थन करने वाली ताकतों का प्रतिरोध भी जारी रहेगा। यह युद्ध विराम फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय संघर्ष में एक स्वागत योग्य राहत होगी। उनका संघर्ष जारी रहेगा और जब तक वह अपने उचित उद्देश्यों को प्राप्त कर नहीं लेते, तब तक वे अधिक से अधिक ताकत जुटाते रहेंगे।

फिलिस्तीनियों के लंबे संघर्ष के इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की नियति को भ्रष्ट और समझौतावादी शाहों और तानाशाहों के हाथों से अपने हाथों में ले लिया है और इसे उक्त शासकों जिनका समर्थन झूठा है जबकि साम्राज्यवाद के प्रति उनकी अधीनता वास्तविक है, के हाथों से छीन लिया है। संघर्ष का यह चरण फिलिस्तीनियों के संघर्ष और उनके वास्तविक समर्थकों के भविष्य को आकार देगा। भारत सहित दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोगों को नरसंहार का पर्दाफाश करना जारी रखना चाहिए और फिलिस्तीनियों के संघर्ष के समर्थन में लोगों को संगठित करते हुए जनसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग करनी चाहिए।

(सीपीआई (एमएल)- न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 19 जनवरी 2025 को जारी)

आपरेशन कगार के विरोध में संयुक्त कार्यक्रम

(पृष्ठ 1 का शेष)

उद्देश्य से यह ऑपरेशन कगार शुरू किया है। हमारा मानना है कि यह नरसंहार का दूसरा नाम है, जो अपनी फासीवादी नीति के तहत आदिवासियों के खिलाफ सीधा सैन्य युद्ध कर रहा है और जंगलों को खूनी युद्ध क्षेत्र में बदल रहा है। हम कगार ऑपरेशन को तत्काल बिना शर्त वापस लेने की मांग करते हैं।

2– पिछले एक वर्ष से बस्तर के अबूझमढ़ के जंगलों में नरसंहार चल रहा है। माओवादियों के बर्बर शिकार के नाम पर फर्जी जवाबी फायरिंग में सैकड़ों आदिवासियों की हत्या की जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि वह तुरंत इसमें हस्तक्षेप करे और इन सभी जघन्य हत्याओं की न्यायिक जांच कराए।

3– हम केंद्र सरकार की उन सभी कार्यवाहियों का विरोध करते हैं, जो आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए अतीत में पारित कई कानूनों, आदेशों, अध्यादेशों को कानून में संशोधन के जरिए धीरे–धीरे कमजोर कर रही है या निरस्त कर रही है। हम मांग करते हैं कि आदिवासियों के अस्तित्व और आजीविका के लिए अतीत में लाई गई सभी कानूनी सुविधाएं बहाल की जाएं।

4– प्रकृति संतुलन और पर्यावरण संरक्षण को सभी लोगों की आम समस्या मानते हुए वनों को सरकारी संपत्ति बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हम यह मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण को कारपोरेट की संपत्ति बनने से होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

5– हम मांग करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू सरकार ऑपरेशन कगार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग न करे। इस गोलमेज बैठक की मांग है कि आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र की संपदा के लिए कारपोरेट से हुए समझौतों को वापस लिया जाए।

6– इस बैठक में भाग लेने वाले राज्य के लोगों, राजनीतिक दलों, जनवादीवादी ताकतों और समूहों को ऑपरेशन कगार को तुरंत वापस लेने की मांग करनी चाहिए और इसके तहत जवाबी गोलीबारी के नाम पर किए गए नरसंहार के विरोध में इस महीने की 13 तारीख को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए।

बैठक में भाग लेने वाले वामपंथी दलों, अधिकार समूहों और जन संगठनों ने भी इस कार्यक्रम के लिए साझा अपील की है। कुछ अन्य दलों और संगठनों ने भी इस कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जो बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए सीपीएम ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य सम्मेलन के कारण भाग लेने में असमर्थ थी।

बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे फासीवाद विरोधी संघर्ष के तहत पार्टियों और संगठनों को एक साथ लाकर इन विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने की योजना बनाई गई है। गोलमेज बैठक में सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी के राज्य प्रतिनिधि पी. प्रसाद और चिट्टीपति वेंकटेश्वरलू, सीपीआई के राज्य सचिव अक्कीनेनी वनजा, नागरिक अधिकार संगठन के राज्य सचिव सीएच चंद्रशेखर, लिबरेशन के राज्य नेता हरनाथ, ओपीडीआर के नेता सी. भास्कर राव, एमसीपीआई (यू) के नेता खादर भाषा, रेड फ्लैग पार्टी के नेता मारेदू प्रसाद, ओपीडीआर के राज्य अध्यक्ष हनुमंत राव, विरसम के अरसावल्ली कृष्णा, एमसीपीआई के गनेश, एचआरएफ के रोहित, के. कृष्ण, केएनपीएस के ताजाराव, प्रोग्रेसिव फोरम के डी भास्कर राव, अमारा वीरूला बंधु मित्रुला संगम, पीओडब्ल्यू से लक्ष्मी, पीडीएम से वेंकटेश्वरलु, सीएलसी से श्रीमन्नारायण, इफ्टू से के पोलारी और अन्य ने भागीदारी की।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

_____

_____

_____

_____

_____

_____

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार